

रजिस्टर्ड नं 011P/13/SML/2003.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 13 फरवरी, 2003/24 माघ, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

आदेश

शिमला-9, 13 फरवरी, 2003

संख्या 7-2/2000-ई0 एल0 एन0.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश संख्या 3/4/आई0 डी0/2003/न्यायिक-II (हि0 प्र0), दिनांक 10 फरवरी, 2003, जिसमें हिमाचल प्रदेश विधान सभा निर्वाचन - 2003 के दौरान आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र के बैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

मनीषा नन्दा,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110 001.

तारीख : 10 फरवरी, 2003

आदेश

संख्या 3/4/आई0 डी0/2003/न्यायिक-II (हि0 प्र0).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उस अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान बनाया जाए; और

2. यतः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और मतदान के समय उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटोग्राफ सहित फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35(3) और 37(2) (ख) में यह अनुबन्ध है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबन्ध के अधीन निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किया गया है उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना पहचान-पत्र जारी करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने और मना करने पर मत-पत्र देने और वोट डालने से उन्हें मना किया जा सकता है; और

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबन्धों के सम्मिलित और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नियमावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहां राज्य की लागत पर आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किया गया है वहां दोनों को ही साथ-साथ प्रयोग में लाया जाना है; और

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था; और

6. यतः, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र कार्यक्रम जारी करने के लिए कार्यान्वयन शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन तन्त्र ने सभी सम्भव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचकों जिनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी हो या वे निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर चले गए हों और उन्होंने मतदाता फोटो पहचान-पत्र कहीं और से प्राप्त कर लिए हों, को ध्यान में रखते हुए पहचान-पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों और इलाकों में चक्रों द्वारा अधिक संख्या में निर्वाचकों को पहचान-पत्र जारी किए हैं; और

7. यतः, जनवरी-मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचनों, अप्रैल-मई, 2001 में हुए केरल, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी के विधान सभाओं के लिए हुए निर्वाचनों, गत वर्ष 2002 में हुए मणिपुर, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा और गुजरात विधान सभा के लिए हुए निर्वाचनों और इस बीच हुए बहुत से उप-निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, मतदान करते समय अपने पहचान-पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन शेष निर्वाचकों जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके; और

8. यतः, उच्चतम न्यायालय को, आर० डी० भंडारी एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में आयोग के उपरोक्त निदेश से अवगत कराया गया और उच्चतम न्यायालय ने मतदाता फोटो पहचान-पत्र सम्बन्धी सभी याचिकाएं 17 अगस्त, 2000 को खारिज कर दी; और

9. यतः, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने क्रमशः 2000 को रिट अर्जी सं० 2598, 2601 और 2637 तथा 2001 की रिट अर्जी सं० 3672 और 2001 की रिट अर्जी सं० 5235, 2002 की रिट अर्जी सं० 294 तथा 2002 की रिट अर्जी सं० 5401 में आयोग के उपर्युक्त निदेशों को क्रमशः मान्य ठहराया है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस०एल०पी० नं० 3820-21/2002 के एक अन्तरिम आदेश पारित किया जिसमें यह निदेश दिया कि जनवरी-फरवरी 2002 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में निर्वाचकों की पहचान के सम्बन्ध में आयोग के आदेश लागू किए जाएं।

10. यतः; अब, सभी सम्बद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निदेश देता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए चालू साधारण निर्वाचनों, जहां मतदान 26 फरवरी, 2003 को होना निश्चित हुआ है मतदान केन्द्र में मत डालने के लिए आते समय और अपने मतदाधिकार का प्रयोग करते समय इन पहचान-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।

11. निर्वाचन आयोग इस बात को दोहराते हुए यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि हिमाचल प्रदेश में चालू साधारण निर्वाचन में निर्वाचकों को निर्वाचन आयोग के प्राधिकार के अधीन जारी निर्वाचक पहचान-पत्रों के माध्यम से मतदान केन्द्र पर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। हालांकि उन्हें मतदान के उद्देश्य के लिए मतदाता पहचान-पत्र का प्रयोग प्रारम्भिक चरणों में है, आयोग इस मामले में पर्याप्त सनकता के रूप में उन शेष निर्वाचकों को चालू साधारण निर्वाचन में मत देने की अनुमति देगा, जिन्होंने मतदाता पहचान-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, बशर्ते उनकी पहचान पीठासीन अधिकारी या दूसरे मतदान अधिकारी, जिसे पीठासीन अधिकारी ने प्राधिकृत किया है, की सन्तुष्टि में अन्यथा स्थापित हो जाती है, उक्त उद्देश्य के लिए उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे निर्वाचकों की पहचान सिद्ध करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं : —

- (i) पासपोर्ट,
- (ii) ड्राइविंग लाइसेंस,
- (iii) आयकर पहचान-पत्र (पी० ए० एन०),
- (iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र,
- (v) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (31-12-2002 को या उससे पूर्व खोला गया खाता),
- (vi) 31-12-2002 को या उससे पूर्व जारी राशन कार्ड,
- (vii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ० जा०/अ० ज० जा०/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र,
- (viii) छात्र पहचान-पत्र,
- (ix) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज आदि,
- (x) शस्त्र लाइसेंस,
- (xi) परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस,
- (xii) पेंशन दस्तावेज जैसा कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश,
- (xiii) भूतपूर्व सैनिक विधवा/अश्रित प्रमाण-पत्र,
- (xiv) रेलवे/बस पास,

- (xv) शारीरिक रूप से अपंगता प्रमाण-पत्र,
- (xvi) स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र,
- (xvii) सरकार द्वारा जारी अधिवासी प्रमाण-पत्र।

12. पहचान के लिए उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेज उन शेष निर्वाचकों, जिन्हें मतदाता पहचान-पत्र सप्लाई तो किए गए हैं किन्तु जिन्हें वे ऐसे कारणों से प्रस्तुत करने में असफल हैं जो उनके बश में नहीं हैं, पर भी लागू होंगे।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर गिनाए गए किसी दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होती है, की परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती है।

आदेश से,

हस्ताक्षरित/-
(धनश्याम खोहर);
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110 001.

Dated, the 10th February, 2003.

ORDER

No. 3/4/ID/2003/J.S.-II(H.P.).—Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of the Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electoral Identity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electoral Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 35 (3) and 37 (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electoral Identity Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electoral Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electoral Identity Cards may result in the denial of supply of a ballot paper to them and permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, Makes it clear that although the right to vote arises by the existence of

the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electoral Identity Card, where provided by the Election Commission at the State cost, and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electoral Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of Himachal Pradesh has issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issuing cards to left-out electors, many of whom might have been dead or might have moved out of the constituencies and obtained their Electoral Identity Cards elsewhere; and

7. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January-March, 2000, and to the Legislative Assemblies of Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Pondicherry in April-May, 2001 and to the Legislative Assemblies of Manipur, Punjab, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Goa and Gujarat held last year and at a number of bye-elections held in between, the Commission had directed that all electors who were issued with EPICs should produce those cards to exercise their franchise at the said elections, and that it would permit the odd electors who have not obtained their EPICs to vote at the said elections, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission; and

8. Whereas, the supreme Court was apprised of the above direction of the Commission in *R. D. Bhandari and Others Vs. Election Commission of India and Others*, and Supreme Court was thereupon pleased to dismiss on 17-8-2000 all petitions relating to the issue of EPICs; and

9. Whereas, the Andhra Pradesh High Court and Punjab and Haryana High Court, Madras High Court, High Court of Madhya Pradesh and High Court of Karnataka have also upheld the above direction of the Commission regarding compulsory identification of electors in Writ Petition Nos. 2598, 2601 and 2637 of 2001, Writ Petition No. 3772 of 2000, Writ Petition No. 5235 of 2001, Writ Petition 294 of 2002 and Writ Petition 5401 of 2002 respectively, and the Hon'ble Supreme Court in the interim order passed on in SLP No. 3820-21/2002, directed that the Commission's Order regarding identification of electors at the general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in January-February, 2002 would be implemented.

10. Now, therefore, after taking in to account all relevant factors and the legal and factual position, the election Commission hereby directs that all electors in the State of Himachal Pradesh, who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current General Election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh, the poll for which is scheduled to take place on 26th February, 2003.

11. The Election Commission wishes to make it clear, at the cost of repetition, that the electors at the current General Election in Himachal Pradesh will have to establish their identity at the polling stations by means of the EPICs issued to them under the authority of the Election Commission. However, since the use of EPICs for the purpose of voting is still in its early stages, the Commission, as a matter of abundant caution, will permit the odd electors who have not obtained their EPICs, to vote at the current General Election, provided their identity is otherwise established to the satisfaction of the Presiding Officer or such other

polling Officer as is authorised by the Presiding Officer in this behalf. For the above purpose they will have to produce some documentary evidence for establishing their identity, and the Commission has prescribed the following alternative documents for establishing the identity of such electors :—

- (i) Passports,
- (ii) Driving Licences,
- (iii) Income Tax Identity (PAN) Card,
- (iv) Service Identity Cards issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local Bodies or other Private Industrial Houses,
- (v) Bank/Kisan/Post Office Passbooks (Accounts opened on or before 31st December, 2002),
- (vi) Ration Cards issued on or before 31st December, 2002,
- (vii) SC/ST/OBC Certificates issued by competent authority,
- (viii) Student Identity Cards,
- (ix) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds, etc.
- (x) Arms Licences,
- (xi) Conductor Licences issued by Transport Authority,
- (xii) Pension Documents such as Ex-Servicemen's Pension Book/Pension Payment Order,
- (xiii) Ex-Servicemen's Widow/Dependent Certificates,
- (xiv) Railway/Bus Passes,
- (xv) Certificate of Physical Handicap,
- (xvi) Freedom Fighter Identity Cards,
- (xvii) Domicile certificates issued by Government.

12. The above alternative documents for identification will also apply in respect of such of the odd electors, who have been supplied with Electoral Identity Cards, but are not able to produce them for reasons beyond their control.

13. It is clarified that any document, as enumerated above, which is available only for the Head of Family, shall be allowed for the purpose of identification of other members of the family. Similarly, any document in the name of any other member of the family could also be used for identification of other members, provided the other members can be identified on the basis of such document.

By order,

Sd/-

(GHANSHYAM KHOHAR),

Secretary.